

Title: Appealed to set up a commission to choose the right place to establish a bench of Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh.

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में पिछले चार महीने से अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर केसेज का अत्यधिक वजन है, न्याय सस्ता और सुलभ हो, इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ कहां स्थापित हो। इस आधार पर जसवंत सिंह कमीशन 1981 में बना और तीन साल तक कमीशन ने बड़ी मेहनत की। कमीशन ने मेहनत करने के बाद 1984 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह रिपोर्ट मेरे पास है। उस रिपोर्ट में पाया गया है कि आगरा सबसे उचित स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अधिवक्ता चार महीने से हड़ताल पर हैं और दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, जिसका समाधान बातचीत से नहीं हो सकता। चाहे मेरठ के अधिवक्ता हों या आगरा के अधिवक्ता हों, सभी ने प्रार्थना की है कि हमारी समस्या को हल किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच आगरा में ही हो सकती है, मेरठ में भी सर्किट बेंच हो सकती है, जहां लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, वह व्यवस्था होनी चाहिए। सदन की जानकारी के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8.5 लाख मामले पेंडिंग हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच आगरा में होनी चाहिए और यदि सर्किट बेंच मेरठ में बनती है, तो कोई आपत्ति नहीं है ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रधान मंत्री जी की सभा में 25 सितम्बर को वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। हिन्दुस्तान में कोई सरकार है या नहीं, क्योंकि सरकार अधिवक्ताओं की समस्या को हल नहीं कर रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार अविलम्ब वकीलों की समस्याओं को हल करे।

सभापति महोदय : अलवी जी, आपने इनके साथ एसोशिएट कर दिया है।

श्री राशिद अलवी : इतना शोर मचाने के बाद सिर्फ एसोशिएट नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी।

सभापति महोदय : नहीं-नहीं, सिर्फ एसोसिएट करिए। वही सब्जैक्ट है।

श्री राशिद अलवी : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर का गरीब आदमी इलाहाबाद में अपना मुकदमा लड़ने के लिए जाता है। हमें सस्ते से सस्ता इंसाफ करना चाहिए। (व्यवधान) वेस्टर्न यूपी में पिछले चार महीनों में 24 सूबों के वकील हड़ताल पर हैं और वे वकील भी कोई मालदार नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे वकील हैं, जिन्हें आर्थिक प्रोब्लम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सब-बेंच मेरे क्षेत्र अमरोहा में भी बना दी जाएगी तो मैं सरकार को फ्री ऑफ कास्ट जमीन देने का प्रबंध करूंगा। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions)*

* Not Recorded